155

(c) The revised guidelines restructuring the old scheme were issued and the revised scheme has become operational only in August 1998. So far no project proposals have been received from Gujarat State.

Statement

Statement showing the Details of Central Promotional Grant/Subsidy and Promoters' Contribution Under Investment Promotional Scheme (IPS)

25%

of

development

activities

on-farm

(A) The details of subsidy

General

Category

(Individual/

(i)

-Group) or Rs. 25 lakhs. whichever is less (ii) Small 30% of on-farm development farmers (Individual/ activities Group) or Rs. 25 lakhs. whichever is less 50% of (iii) (a)

whichever is less
(iii) (a) 50% of on-farm
Marginal development
Farmers activities
(Individual/ or Rs. 25 lakhs,
Group) whichever is less

- (b) SC/ST Same as A (iii) (a)
 Farmers above
 without any
 limit in the
 arca of
 holdings
 (Individual/
 Group)
- (B) Details of promoters' contribution
- (i) General Category. (Individual/

At least 25% of the project cost.

Group)

(ii) Small At least 10% of the farmers project cost.

(Individual/

Group)

(iii) (a)
Marginal
Farmers
(Individual/
Group)

Nil, however, at the time of execution of the project, the family labour should be involved to provide selfemployment

ensuring
participation.
Same as B(iii) (a)

above.

(b) SC/ST Farmers without any limit in the area of holdings (Individual/ Group)

गांवों को मूलभूत सुविधायें 2762. श्री राज मोहिन्दर सिहः

श्री राज मीहिन्दर सिंहः
 श्री बलवत्त सिंह रामूवालियाः

क्या प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अकंतूबर, 1998 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'मेक डेवलपमेंट विलेज-सेन्ट्रिक" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गांवों में मुलभुत सुविधायें न होने के कारण देश का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा: और

Written Answers

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और मलभत सिवधायें उपलब्ध करवाने के लिए समय सीमा के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) और (ख) जी. हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सड़क को पक्का किया जाना

2763. श्री मनव्वर हसनः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले में ब्लाक ठेकमा में भगवानपुर से भगौतीपुर के बीच में मार्ग को पिछले 50 वर्षों से पका नहीं किया गया है:
- (ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस सडक को पक्का करने के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ग) सडकों के निर्माण और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। "विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सडकें" नामक कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय अध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में केवल डकैती बहल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए अनुदान पर विचार करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में ठेकमा ब्लाक में भगवानपुर से भगौतीपुर के बीच सडक को पक्षा करने की कोई योजना या कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। *

Identification of 100 most backward and poorest districts

2764. SHRI **BRAHMAKUMAR** BHATT: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- whether Government appointed a Committee in the recent past to evolve criteria for identification of 100 most backward and poorest districts in the country;
 - (b) if so, the details thereof;
- (c) whether identification of such districts has since been made; and
 - (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Yes, Sir. The Government had appointed a Committee under the Chairmanship of Dr. E.A.S. Sarma (presently Secretary, Expenditure) 1997 to evolve criteria identification of 100 most backward and poorest districts and identify districts. Other Members Committee were Dr. Prnab Sen Adviser. Planning Commissioner, Dr. Rohini Nayyar, Advisor Planning Commission, Prof. K.L. Krishna Delhi School of Economics and Shri Satish Chandra Joint Secratry, Ministry of Rural Areas & **Employment**

(c) and (d) Yes, Sir. The List of districts identified by the Committee is given in the enclosed statement.

Statement

List of the 100 most backward and poorest districts (State-wise)

BIHAR

- 1. Nalanda
- 2. Bhojpur
- 3. Ranchi
- 4. Aurangabad
- 5. Jehanabad
- 6. Gaya
- 7. Nawada
- 8. Saran
- 9. Siwan
- 10. Gopalganj
- 11. Paschim Champaran